S.No.	State	Name
16.	West Bengal	Justice S.K. Hazari
17.	North East	Justice K.N. Saikia Justice Trun Das

छत्तीसगढ़ जिले में रसोई गैस के कनेक्शन

1360. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले में रसोई गैस (एल पी जी) की एजेंसियां किन-किन स्थानों पर कब से स्थापित हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक इन एजेंसियों को रसोई गैस के वर्ष-वार कितने अतिरिक्त कनेक्शन प्रदान किए गए;

(ग) इन एजेंसियों के पास नए कनेक्शन प्राप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत हैं; और

(घ) जारी किए गए अतिरिक्त कनेक्शनों तथा प्रतीक्षा सूची में दर्ज की संख्या का एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालु): (क) से (घ) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 62 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें हैं। उनकी संख्या, वयोवर्ग, 1990-91 से 1996-97 के वर्षों के दौरान जारी किए गए कनेक्शनों तथा जनवरी, 1997 की प्रतीक्षासूची को निर्दिष्ट करता हुआ ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है:—

कंपनी	संख्या	वयोवर्ग	जारी किए गए कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची
आई०ओ०सी०	28	1972—96	27110	46107
एच पी सी एल	27	1963—96	28265	53282
बी पी सी एल	7	1984—95	17286	16253
योग	62	1963—96	72661	115642

Import of Oil From Iraq

1361. SHRI K.R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India did not place any orders for Iraqi oil for four months after the UN embargo on the export of Iraqi Oil was lifted; and

(b) whether the country has lost $ 120 million on oil imports as a result of this delay, as reported in the Economic Times dated the 31st January, 1997 and in the Statesman dated the 2nd September, 1996?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T. R. BALLU): (a) and (b) UNO had permitted limited export sales of crude oil from Iraq from 10.12.1996 for a period of 6 months, under oil for Food Plan. IOC, the sole canalising agency for importing the crude oil to India, has alredy finalised a contract with M/s. Somo of Iraq for import of 0.5 MMT Basrah light curde oil during this period, with the approval of the designated UN committee, as per provisions of UNO's oil for Food Plan.